



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244764
CG-DL-E-29032023-244764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 71]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

मामला संख्या: ओआई -17/2022

विषय: चीन जन.गण. तथा थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोले" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. **फा. संख्या 6/17/2022-डीजीटीआर.**—1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "ए डी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।
2. मै. मनाली पैट्रोकेमिकल्स लि., ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान,

उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. तथा थाइलैंड (जिन्हें यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल (जिसे आगे “एफएसपी” भी कहा गया है), है। यह एक क्लियर विस्कोस लिक्विड पॉलीमर है जिसका आणविक भार 3000-4000 होता है तथा जिसे एक ट्रायोल चैन स्टार्टर अर्थात् प्रोपीलीन ऑक्साइड और एथीलीन ऑक्साइड एक पालीमराइजेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है। यह एक पॉलीईथर है और उत्प्रेरकों एडिटिव्स के साथ प्रतिक्रिया करके पॉलीयूरेथीन फॉम बनाता है जिनका उपयोग अपहोलस्ट्री, गद्दों, तकियों, बोलस्टर्स, ट्रांसपोर्ट सिटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है। इसे टैंकरों में परिवहन किया जाता है या स्टील के ड्रमों में भंडारित किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई समर्पित वर्गीकरण कोड नहीं है। इसे अध्याय शीर्ष 39 “प्लास्टिक्स और आर्टिकल” के अंतर्गत आयातित किया जाता है और चार अंकीय स्तर पर इसका वर्गीकरण 3907 है। 6 अंकीय स्तर पर संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के उपशीर्ष 3907 20, 3907 29, 3907 99 जैसे विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत आयातित किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि पीयूसी के आयातों को विभिन्न अन्य उप शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है।
5. जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के जारी होने से 20 दिनों के भीतर, पीसीएन के निर्माण के लिए, यदि कोई प्रस्ताव हो, तो अपने प्रस्ताव प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। चीन जन. गण. और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. तथा थाइलैंड से भारत के घरेलू बाजार में आने वाली वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषज्ञताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मै. मनाली पेट्रोकेमिकल लि. द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में समान वस्तु का एकमात्र घरेलू उत्पादक है और इसलिए कुल घरेलू उत्पादन में उसका 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. और थाइलैंड में उनका कोई संबंधित पक्षकार नहीं है और न ही उन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तदनुसार उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह माना जाता है कि आवेदक ए डी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर

घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मापदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

8. यह आवेदन चीन जन.गण. तथा थाइलैंड (जिन्हें यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में किया गया है।

ड. जांच की अवधि

9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 (12 माह) की है। जांच क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच अवधि (पी ओ आई) की अवधियों पर विचार किया गया है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. से उत्पादकों का सामान्य मूल्य चीन जन.गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है, जबकि संबद्ध देश के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाते हों कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देते हैं, ऐसा नहीं होने पर संबद्ध देश से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य ए डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
11. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश या अपनाए गए अन्य वैकल्पिक तरीकों के अनुसार लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े इस स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने बताया है कि वह इस स्तर पर चीन जन.गण. के लिए किसी प्रतिनिधि देश का पता लगाने में भी सक्षम नहीं है। इसके अलावा, भारत को गैर- पाटन तीसरे देश/देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा नगण्य है। अतः सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है।

ii. थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

12. थाइलैंड के संबंध में आवेदक ने बताया है कि उसने थाइलैंड के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए थे। आवेदक ने थाइलैंड से अन्य देशों को निर्यातों के लिए निर्यातकों की कीमत सूची या कीमत साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास भी किए थे, परंतु वह कोई सटीक और विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि संबद्ध वस्तु के लिए कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसके अलावा, भारत को गैर-पाटन तीसरे देश/देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा नगण्य है। अतः सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के

अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है।

iii. निर्यात कीमत

13. आवेदक ने संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा गौड़ स्रोत के आंकड़ों में सूचित सी आई एफ कीमत पर विचार करते हुए किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन संभलाई और निकासी प्रभारों, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। चीन जन. गण. से निर्यातों के मामले में वैट भी समायोजित किया गया है।

छ. पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन सिद्ध करती हैं। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कीमत ह्रास, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोजित ठहराते हैं।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को प्रथमदृष्टया संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबंध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए एतद्वारा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. प्रक्रिया

17. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6 के अंतर्गत यथानिर्धारित सिद्धांतों का पालन किया गया है।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों jd12-dgtr@gov.in, और ad12-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv13-dgtr@gov.in. पर ई-मेल से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोधों का वर्णनात्मक हिस्सा केवल पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल केवल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
19. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के ज़रिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना के खंड 8 में उल्लिखित समय-सीमा या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अनुरोध इस जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग से इस जांच शुरुआत अधिसूचना के खंड 8 में उल्लिखित समय सीमाओं या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर इस जांच शुरुआत अधिसूचना के खंड 9 के अनुसार निर्धारण किया जाएगा।
22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि संबद्ध जांच में आगामी गतिविधियों के बारे में अवगत रहने और प्रश्नावली के प्रपत्र, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक के कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि पत्र, संशोधन अधिसूचना, समय सीमाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के संबंध में अवगत रहने के लिए वे नियमितरूपसे व्यापार उपचारमहानिदेशालय की वैबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in>) को देखते रहें। इससे सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी के बारे में भली भांति जागरूक रहेंगे। किसी पक्षकार को सूचना नहीं मिलने का कोई विशिष्ट मामला वैबसाइट पर अद्यतन की गई सूचना को अवैध करार देने का आधार नहीं होगा।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों के पंजीकरण और उत्तर/अनुरोध/सूचना देने के लिए समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई उत्तर/अनुरोध/सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पत्तों jd12-dgtr@gov.in, और ad12-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv13-dgtr@gov.in. पर ईमेल के माध्यम से एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति

या व्यापार उपचार महानिदेशालय (जिसे आगे डीजीटीआर कहा गया है) की वैबसाइट में ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख, जो भी बाद में हो, से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने या डीजीटीआर की वैबसाइट पर उसके प्रकाशन, जो भी बाद में हो, की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना के खंड 6 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और ऊपर यथानिर्धारित समय सीमा या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा अलग से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
25. जहां कहीं कोई हितबद्ध पक्षकार उत्तर/अनुरोध/सूचना देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा अलग से निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
27. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
28. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी, जो स्वभाव से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसके सूचना प्रदाता ने उसके गोपनीय होने का दावा किया है। स्वभाव से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों की वजह से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के संबंध में ऐसी सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ इस बात का पर्याप्त और पूर्ण कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय रूपांतरण अनिवार्य रूप से उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और एडी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं।
31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. प्रस्तुत सूचना/अनुरोध/उत्तर के गोपनीय स्वरूप के संबंध में पर्याप्त और पूर्ण कारणों से संतुष्ट होने पर प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार कर सकते हैं और वे ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
33. प्रस्तुत सूचना/अनुरोध/उत्तर के गोपनीय स्वरूप के संबंध में पर्याप्त और पूर्ण कारणों से संतुष्ट होने पर प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार कर सकते हैं और वे ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड-ण के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

ण. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

Case No. OI - 17/2022

Subject: Initiation of an Anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from China PR and Thailand.

1. **F. No. 6/17/2022-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules).
2. M/s Manali Petrochemicals Ltd., has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD Rules”) for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as the “subject goods”) originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”).

A. Product under consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as “FSP”). It is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams that are used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. It is transported in tankers or stored in steel drums.
4. The PUC does not have a dedicated classification code under the Customs Tariff Act, 1975. It is imported under Chapter Heading 39 “Plastics and Articles” and its classification at the 4-digit level is 3907. At the six-digit level, the subject goods are being classified and imported under various sub-headings like 3907 20, 3907 29, 3907 99 of Schedule-I of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification code is indicative only and is not binding on the scope of the PUC as the imports of the PUC may be reported under various other subheadings.
5. All interested parties to the investigation may provide their proposal for construction of PCNs, if any, within 20 days from the issue of this notification

B. Like Article

6. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences between the subject goods exported from China PR and Thailand and the goods produced by the applicant. The goods produced by the domestic industry and originating in or exported from China PR and Thailand into the domestic market of India are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The consumers have used and are using the two products interchangeably. For the purpose of the present investigation, the goods produced by the domestic industry are being treated as ‘like article’ to the subject goods imported from the subject countries.

C. Domestic Industry and Standing

7. The application has been filed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd on behalf of the domestic industry. The applicant has claimed that it is the sole domestic producer of the like article in India and therefore, accounts for 100 % share of the total domestic production. The applicant has submitted that they do not have any related party in China PR and Thailand nor have they imported the subject goods during the POI from the subject countries. Accordingly, as per the available information, it is held that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the AD Rules.

D. Subject countries

8. The application has been filed in respect of the alleged dumping of the product under consideration from China PR and Thailand (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

E. Period of Investigation

9. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January 2022 to 31st December, 2022 (12 months). For the purpose of analyzing injury, the periods 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation (POI) have been considered.

F. Basis of Alleged Dumping**i. Normal Value for China PR**

10. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and para 7 of the Annexure I to the AD Rules, the normal value of producers from China PR may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR only if the responding producers from the subject country demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure I to the AD Rules, failing which, normal value for the producers from the subject country must be determined in accordance with paras 7 and 8 of Annexure I to the AD Rules.
11. The applicant has submitted that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse other alternative methods is not available at this stage. The applicant has submitted that it has not been able to ascertain any surrogate country for China PR at this stage. Further, the import volume of the subject goods from a non-dumping third country/country to India is negligible. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of production of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin. The normal value has been computed based on the cost of production of the domestic industry after duly the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

ii. Normal Value for Thailand

12. With respect to Thailand, the applicant has submitted that it had made efforts to acquire information regarding prices of the subject goods in the domestic market of Thailand. The applicant also attempted to obtain price list of the exporters or price evidence for the export to other countries from Thailand but was not able to find any accurate and reliable information as there is no dedicated HS code for the subject goods. Further, the import volume of the subject goods from a non-dumping third country/country to India is negligible. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of production of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin. The normal value has been computed based on the cost of production of the domestic industry after duly the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

iii. Export Price

13. The applicant has claimed export price of the subject goods by considering the CIF reported in the secondary source data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, commission, credit cost and bank charges. In case of exports from China PR VAT has also been adjusted.

G. Dumping Margin

14. The normal value and the export price, have been compared at ex-factory level which prima facie establishes a dumping margin above the de-minimis level in respect of the subject goods from the subject countries. Thus, there is sufficient prima facie evidence, that the subject goods are being dumped into the domestic market of India by the producers/exporters from the subject countries.

H. Injury and Causal Link

15. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price suppression, decline in market share of the domestic industry, profitability, cash profits and return on capital employed. The Authority, based on the information submitted by the applicant, is of the view that there is sufficient prima facie evidence of the injury being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

I. Initiation of Anti-Dumping Investigation

16. On the basis of a duly substantiated written application filed by the domestic industry, and having reached a prima facie satisfaction, based on the prima facie evidence submitted by the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and the

consequential injury to the domestic industry as a result of the dumping of the subject goods, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duties, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. Procedure

17. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

K. Submission of information

18. All communications should be sent to the Designated Authority via email at jd12-dgtr@gov.in, and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in, and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submissions is in searchable PDF / MS word format only and data files are in MS Excel format only.
19. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users of the subject goods in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in Section L of this Initiation Notification or timelines established by the Authority during the investigation. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.
20. Any other interested party may also make its submissions that are relevant to the investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in Section L of this Initiation Notification or timelines established by the Authority during the investigation.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same which will be made available to the other parties. Failure to do so would lead to determination in accordance with Section O of this Initiation Notification.
22. Interested parties are further directed to regularly visit the website of Directorate General of Trade Remedies (<https://dgtr.gov.in/>) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, timelines and other such information. This will ensure that all interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation. Specific non-intimation of information to any party shall not be a ground to invalidate the information updated on the website.

L. Time Limit for Registration of Interested Parties and Filing of Responses/Submissions/Information

23. Any response/submission/information pertaining to the present investigation and any request for hearing should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd12-dgtr@gov.in, and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in, and adv13-dgtr@gov.in, within thirty days (30 Days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the AD Rules, or publication on such notice at the Directorate General of Trade Remedy's (hereinafter referred to as DGTR) website, whichever is later. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries or on its publication on the DGTR website, whichever is later. If no information is received within the prescribed time-limit or if the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with Section O of this Initiation Notification.
24. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the present matter and file their questionnaire responses within the time limit stipulated above or timelines established separately by the Authority during the investigation.
25. Where an interested party seeks additional time for filing of responses/submissions/information, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this Initiation Notification or timelines established separately by the Authority during the investigation.

M. Submission of information on confidential basis

26. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued

by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

27. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. With respect to information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a sufficient and adequate cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
30. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied with sufficient and adequate reasons regarding the confidential nature of the information/submission/response may accept the need for confidentiality of the information provided, and shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non – confidential version of submissions/response/information might lead to action under Section O of this Initiation Notification

O. Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority